



UNFCCC कॉन्फरेंस ऑफ पार्टीज (COP)





UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP)

UNFCCC Conference of Parties (COP)



परिचय:

- UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय
- प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है (जब तक कि पश्च अन्यथा निर्णय न ले)
- बॉन, सचिवालय में आयोजित होता है (जब तक कि कोई पश्च सत्र की मेज़बानी करने की पेशकश न करे)
- पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) - बर्लिन, जर्मनी में आयोजित (1995) हुआ

COP और उनके परिणाम

COP 3 (1997)
क्योटो, जापान

- क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया (विकसित देशों को उत्सर्जन लक्ष्य कम करने के लिये विधिक रूप से बाध्य किया)

COP 7 (2001)
मारकेश, मोरक्को

- मारकेश समझौते पर हस्ताक्षर (क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसर्थन के लिये मंच तैयार)

COP 8 (2002)
नई दिल्ली, भारत

- दिल्ली घोषणा (अति निर्धन देशों के विकास की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया)

COP 13 (2007)
बाली, इंडोनेशिया

- बाली रोड मैप और बाली एकशन प्लान

COP 15 (2009)
कोपेनहेंगन, डैनमार्क

- विकसित देशों ने 30 विलियन डॉलर तक के फास्ट-स्टार्ट फाइनेंस (2010-12 के लिये) का वादा किया

COP 16 (2010)
कानकुन, मेक्सिको

- कानकुन समझौते पर हस्ताक्षर (क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसर्थन के लिये मंच तैयार)

COP 18 (2012)
दोहा, कतर

- दिल्ली घोषणा (अति निर्धन देशों के विकास की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया)

COP 19 (2013)
वारसां, पोलैंड

- बाली रोड मैप और बाली एकशन प्लान

COP 21 (2015)
पेरिस, फ्रांस

- पेरिस समझौता (वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक समय से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे)
- अमेरिका देशों द्वारा जलवायु वित्त (वार्षिक \$100 बिलियन फंडिंग प्रतिज्ञा)

COP 26 (2021)
ग्लासगो, यूके

- भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य की घोषणा की
- भारत ने कोयला आधारित विद्युत को “चरणबद्ध तरीके से कम करने” का आह्वान किया
- ग्लासगो ब्रेकथ्रू एजेंडा (41 देशों + भारत द्वारा)
- COP 27 (2022) - शर्म-अल-शेख (Sharm-el-Sheikh), मिस्र
- लॉस एंड डैमेज फंड
- पूर्व चेतावनी प्रणालियों के लिये 3.1 विलियन अमेरिकी डॉलर की योजना
- जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों के लिये G7 के नेतृत्व वाली ‘ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग सुविधा’
- अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल
- जल अनुकूलन और लचीलापन (AWARe) पहल के लिये कार्रवाई
- मैयोव एलायंस (भारत की साझेदारी के साथ)
- भारत की दीर्घकालिक न्यूनतम उत्सर्जन विकास रणनीति

COP 28 (2023)
दुबई, यूएई

- UAE, जर्मनी, UK, EU और जापान ने लॉस एंड डैमेज फंड के लिये 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया
- वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य हासिल करने के लिये जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना
- वर्ष 2030 तक 11,000 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करना
- वर्ष 2050 तक 66 देश शीतलन उत्सर्जन में 68% की कटौती करने का लक्ष्य
- वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करना
- COP 28 में भारत द्वारा की गई पहल:
 - हरित क्रण पहल: बंजर भूमि पर पौधे लगाने जैसे पर्यावरण
 - अनुकूल कार्बन के लिये क्रण जारी करना
 - LeadIT 2.0: निष्पक्ष उद्योग परिवर्तन और न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी का समर्थन करता है
 - ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस (GRCA): सतत नदी विकास और सर्वोत्तम अभ्यास साझाकरण को बढ़ावा देता है
 - क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप (QCWG): स्थानीय और क्षेत्रीय स्थिरता प्रयासों को बढ़ाता है

COP 29 नवंबर 2024 में बाकू, अज़रबैजान में आयोजित किया जाएगा।

